**International Journal of Research in Social Sciences**
Vol. 8 Issue 9, September 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

# महिला उद्यमिता: भारत के आर्थिक विकास की रीढ़

**डॉ. रमेश चन्द्र**
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग
महामाया राजकीय डिग्री कॉलेज, कौशांबी

**सारांश**

वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में महिला उद्यमिता एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आ रही है। यह शोध-पत्र महिला उद्यमिता की भूमिका को आर्थिक विकास के एक प्रमुख कारक के रूप में प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा महिलाएँ हैं, वहाँ उनका आर्थिक रूप से सक्रिय होना न केवल सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि यह राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को भी गति प्रदान करता है।

शोध का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि किस प्रकार महिलाएं पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs), सेवा क्षेत्र, हस्तशिल्प, ई-कॉमर्स, कृषि आधारित उद्योगों आदि में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। साथ ही यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले कौन-कौन से सामाजिक, संस्थागत, और सरकारी तत्व हैं और किन संरचनात्मक चुनौतियों के कारण इनकी प्रगति सीमित रह जाती है।

इस शोध-पत्र में आंकड़ों, केस स्टडीज़ और नीतिगत दस्तावेज़ों के आधार पर यह बताया गया है कि महिला उद्यमिता का विकास न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, लैंगिक असमानता को कम करने और एक समावेशी आर्थिक प्रणाली की स्थापना में भी योगदान करता है।

सरकारी योजनाओं जैसे कि "मुद्रा योजना", "स्टार्टअप इंडिया", "महिला शक्ति केंद्र", और राज्य-स्तरीय महिला विकास निगमों की भूमिका का विश्लेषण इस शोध का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। साथ ही यह भी बताया गया है कि सामाजिक पितृसत्तात्मक संरचना, वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण एवं बाज़ार तक पहुँच जैसी बाधाएँ आज भी महिला उद्यमियों के मार्ग में बड़ी रुकावटें हैं।

अंततः, यह शोध सुझाव देता है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है — जिसमें नीति निर्माण, वित्तीय समर्थन, शिक्षा और प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता तथा तकनीकी सुविधाओं का एकीकृत ढांचा शामिल हो।

**मुख्य शब्द:** महिला उद्यमिता, आर्थिक विकास, समावेशी विकास, हस्तशिल्प, मुद्रा योजना, नीति निर्माण

**International Journal of Research in Social Sciences**
Vol. 8 Issue 9, September 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

## 1.0 परिचय

महिला उद्यमिता उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें महिलाएं स्वतंत्र रूप से या सह-स्वामित्व में किसी उद्यम, व्यवसाय या सेवा को स्थापित, प्रबंधित और विकसित करती हैं। यह न केवल एक आर्थिक गतिविधि है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का साधन भी है।

**भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)** के अनुसार, "वह महिला जो किसी उद्यम में न्यूनतम 51% पूंजी का स्वामित्व रखती हो तथा उसका संचालन करती हो, महिला उद्यमी मानी जाती है।"

महिला उद्यमिता पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर नवाचार, सेवा क्षेत्र, तकनीकी स्टार्टअप, कुटीर उद्योग, कृषि-आधारित व्यवसाय, तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स में सक्रिय रूप से भाग ले रही है।

### 1.1 अध्ययन की आवश्यकता (Need for the Study)

महिला उद्यमिता पर अध्ययन की आवश्यकता आज के समय में इसलिए है क्योंकि:

- महिलाएं समाज की आधी जनसंख्या हैं, फिर भी आर्थिक भागीदारी में उनका प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है।
- भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की उद्यमशीलता न केवल उनके सशक्तिकरण का माध्यम बनती है, बल्कि यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में भी सहायक है।
- मौजूदा आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या 20% से भी कम है, जबकि OECD देशों में यह आँकड़ा अधिक है।
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ और नीतियाँ तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन और प्रभाव का विश्लेषण अपर्याप्त है।
- सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ, पूंजी तक पहुँच, शिक्षा की कमी और तकनीकी ज्ञान की सीमित उपलब्धता के चलते महिला उद्यमिता में वांछित वृद्धि नहीं हो पा रही है।

### 1.2उद्देश्य (Objectives of the Study)

इस शोध का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. भारत में महिला उद्यमिता की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
2. महिला उद्यमियों द्वारा किए गए आर्थिक योगदान की पहचान करना।
3. महिला उद्यमिता की राह में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन करना।
4. सरकारी योजनाओं, नीतियों एवं संस्थागत समर्थन का मूल्यांकन करना।
5. महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ प्रस्तुत करना।

## 2. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 9, September 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

### 2.1 उद्यमिता का आर्थिक विकास में महत्व

उद्यमिता किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का मूल आधार होती है। यह न केवल नवाचार को जन्म देती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करती है। उद्यमी वर्ग संसाधनों का बेहतर उपयोग कर उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और बाज़ार में नई प्रतियोगिता को जन्म देता है। आर्थिक विकास में उद्यमिता का महत्व इस बात में निहित है कि यह पूंजी निर्माण, निर्यात संवर्धन, और क्षेत्रीय विकास को सशक्त बनाती है। एक सशक्त उद्यमशील तंत्र सामाजिक परिवर्तन लाता है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य करता है।

### 2.2 महिला-केन्द्रित विकास सिद्धांत

महिला-केन्द्रित विकास सिद्धांत यह मानता है कि किसी भी राष्ट्र का समावेशी विकास तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाएं उसकी आर्थिक और सामाजिक संरचना में समान रूप से भाग नहीं लेतीं। महिला विकास को केवल कल्याण या सहायता का विषय न मानते हुए यह दृष्टिकोण महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम नागरिक के रूप में स्थापित करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन के उत्प्रेरक (change agents) के रूप में देखा जाना चाहिए। उद्यमिता महिलाओं के लिए वह साधन बन सकता है जिससे वे अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकती हैं।

### 2.3 वैश्विक बनाम भारतीय परिप्रेक्ष्य

विश्व स्तर पर महिला उद्यमिता को सशक्तिकरण का माध्यम माना गया है और विकसित देशों में महिलाओं को पूंजी, प्रशिक्षण, और बाज़ार तक व्यापक पहुँच उपलब्ध है। इसके विपरीत भारत में महिला उद्यमिता का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। हालांकि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई गई हैं, परंतु सामाजिक मान्यताएँ, शिक्षा की कमी, वित्तीय रुकावटें और संस्थागत समर्थन की सीमितता अभी भी महिला उद्यमिता के मार्ग में बड़ी बाधाएँ बनी हुई हैं। वैश्विक तुलना में भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला उद्यमिता को अधिक समर्पित रणनीति, नीति निष्पादन और सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है।

## 3. महिला उद्यमिता का वर्तमान परिदृश्य

### 3.1 भारत में महिला उद्यमिता की स्थिति

भारत में महिला उद्यमिता धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रही है। राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षणों और रिपोर्टों के अनुसार, कुल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) में से लगभग 20% महिला स्वामित्व वाले हैं। अधिकतर महिलाएं घरेलू, हस्तशिल्प, कृषि-आधारित या सेवा क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों में सक्रिय हैं। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ रहा है, फिर भी यह

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 9, September 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

संभावनाओं की तुलना में कम है। महिलाओं की भागीदारी अब ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थकेयर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी दिखने लगी है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, और महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म ने महिलाओं को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन वित्तीय पहुँच, बाजार जानकारी और सामाजिक समर्थन अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

### 3.2 ग्रामीण और शहरी परिप्रेक्ष्य

ग्रामीण और शहरी भारत में महिला उद्यमिता की प्रकृति और चुनौतियाँ अलग-अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मुख्यतः स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के माध्यम से व्यवसाय करती हैं जैसे कि बुनाई, सिलाई, हस्तशिल्प, जैविक खेती, दुग्ध उत्पादन और घरेलू उत्पाद निर्माण। यहां शिक्षा की कमी, सीमित संसाधन और सामाजिक बंधन बड़ी रुकावट हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाएं तकनीक-आधारित स्टार्टअप्स, रिटेल, ब्यूटी एवं वेलनेस, डिजिटल सेवाओं तथा कंसल्टेंसी में अधिक सक्रिय हैं। शहरी महिला उद्यमियों को पूंजी, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग की बेहतर सुविधा मिलती है, लेकिन यहां कार्य-जीवन संतुलन और प्रतिस्पर्धा बड़ी चुनौतियाँ हैं। दोनों परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि महिला उद्यमिता सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बन रही है।

### 3.3 सफल महिला उद्यमियों के केस स्टडीज़

भारत में कई महिला उद्यमियों ने अपने नवाचार, नेतृत्व और संघर्ष के माध्यम से समाज में प्रेरणा का स्रोत बनकर दिखाया है। उदाहरणस्वरूप, कल्पना सरोज, जिन्होंने दलित पृष्ठभूमि से निकलकर "कामानी ट्यूब्स" जैसी बड़ी कंपनी का नेतृत्व किया, महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। फाल्गुनी नायर, जिन्होंने नायका (Nykaa) की स्थापना की और उसे एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाया, आधुनिक महिला नेतृत्व का प्रतीक हैं। राधिका अग्रवाल (ShopClues) और श्रद्धा शर्मा (YourStory) जैसी महिला उद्यमियों ने तकनीक और मीडिया के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति को सशक्त किया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि अवसर और समर्थन मिले, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती हैं। ये केस स्टडीज़ यह भी दर्शाती हैं कि महिला उद्यमिता अब प्रेरणास्पद कहानियों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक बदलाव की दिशा में अग्रसर है।

## 4. आर्थिक विकास में योगदान

### 4.1 GDP में योगदान

महिला उद्यमिता भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सकारात्मक योगदान देने की क्षमता रखती है। रिपोर्टों के अनुसार, यदि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को पुरुषों के समान स्तर तक बढ़ाया जाए, तो भारत की GDP 16% से अधिक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि वर्तमान में महिला-स्वामित्व वाले उद्यम मुख्यतः सूक्ष्म स्तर पर कार्यरत हैं और उनका कुल GDP में योगदान सीमित है, फिर भी इनका व्यापक सामाजिक प्रभाव है। ऐसे उद्यम ग्रामीण उत्पादन, शहरी सेवा क्षेत्रों,

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 9, September 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कृषि प्रसंस्करण, और घरेलू उद्योगों में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। आने वाले वर्षों में यदि नीति-समर्थन और संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, तो महिला उद्यमिता राष्ट्रीय आर्थिक संरचना का मजबूत आधार बन सकती है।

### 4.2 रोज़गार सृजन

महिला उद्यमिता रोजगार सृजन का एक शक्तिशाली माध्यम है, विशेष रूप से अनौपचारिक एवं स्थानीय स्तर पर। महिला उद्यमी न केवल स्वयं को रोजगार प्रदान करती हैं, बल्कि अन्य महिलाओं, प्रशिक्षित कारीगरों, विक्रेताओं और आपूर्ति श्रृंखला के श्रमिकों को भी कार्य के अवसर देती हैं। महिला-स्वामित्व वाले कई स्टार्टअप्स और कुटीर उद्योगों ने सैकड़ों लोगों को स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित इकाइयाँ स्थानीय महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार महिला उद्यमिता बेरोजगारी को कम करने, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने का सशक्त औजार है।

### 4.3 सामाजिक सशक्तिकरण

महिला उद्यमिता केवल आर्थिक परिवर्तन का माध्यम नहीं है, यह गहरा सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, तो वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय होती हैं — चाहे वह परिवार हो, समुदाय हो या पंचायत स्तर की राजनीति। इससे सामाजिक भूमिका में बदलाव आता है और पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती मिलती है। महिला उद्यमिता शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बालिकाओं की सुरक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ आत्म-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता में भी वृद्धि होती है। विशेष रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए उद्यमिता एक सशक्त सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकती है।

## 5. मुख्य चुनौतियाँ

### 5.1 पूंजी की कमी

महिला उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूंजी या वित्तीय संसाधनों की कमी है। अधिकांश बैंक और वित्तीय संस्थान महिलाओं को ऋण देने में हिचकिचाते हैं, खासकर जब उनके पास संपत्ति गिरवी रखने की गारंटी नहीं होती। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को निवेशकों और फंडिंग नेटवर्क तक पहुँच भी अपेक्षाकृत कम होती है। ग्रामीण और अल्प-शिक्षित महिलाएं वित्तीय दस्तावेज़ों और प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई महसूस करती हैं, जिससे उन्हें संस्थागत सहायता प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। पूंजी की यह कमी उनके व्यवसाय के विस्तार, नवाचार और प्रतिस्पर्धी क्षमता को सीमित कर देती है।

### 5.2 सामाजिक-सांस्कृतिक रुकावटें

भारत जैसे पारंपरिक समाज में महिला उद्यमिता को सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परिवार और समाज की अपेक्षाएँ प्रायः महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित कर देती हैं। व्यवसाय

करने वाली महिलाओं को अकसर संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ता है, खासकर यदि वे लंबे समय तक घर से बाहर रहती हैं या पुरुषों के साथ कार्य करती हैं। कई बार महिलाओं को अपने उद्यम की अनुमति के लिए परिवार या पति पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे सामाजिक दबाव उनके आत्मविश्वास और निर्णय-निर्माण क्षमता को प्रभावित करते हैं।

### 5.3 शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की कमी

महिलाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की अनुपलब्धता एक गंभीर चुनौती है। कई महिलाएं व्यवसाय प्रारंभ तो कर लेती हैं, लेकिन वित्तीय प्रबंधन, विपणन, डिजिटल तकनीक और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव में उनका विकास रुक जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा दर कम होने से उनकी उद्यमशीलता क्षमता को समुचित दिशा नहीं मिल पाती। सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुँच भी सीमित है या उनमें व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी होती है। परिणामस्वरूप, महिलाएं प्रतिस्पर्धी बाज़ार में टिक नहीं पातीं और उनके व्यवसाय अल्पकालिक रह जाते हैं।

## 6. नीतिगत सुझाव और सरकारी योजनाएँ

### 6.1 स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना आदि

भारत सरकार ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इनमें स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिला शक्ति केंद्र, महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म (WEP), और दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) प्रमुख हैं।

स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत महिलाओं को नवाचार आधारित व्यवसाय स्थापित करने हेतु कर में छूट, पंजीकरण में सुविधा और स्टार्टअप हब से परामर्श जैसी सेवाएँ दी जाती हैं।

मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए तीन श्रेणियों में ऋण (शिशु, किशोर, तरुण) प्रदान किए जाते हैं, जिनमें बिना गारंटी ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है।

महिला शक्ति केंद्र योजना का उद्देश्य जिला स्तर पर महिलाओं को सूचना, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकें।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने भी कई योजनाएँ जैसे कि "उद्यमिता विकास कार्यक्रम", "महिला कौशल विकास मिशन" और "लखपती दीदी योजना" शुरू की हैं जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार महिला उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं।

### 6.2 महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की नीति-नीति विश्लेषण

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की नीतियाँ अभी तक अधिकतर प्रोत्साहन आधारित रही हैं, जिनमें ऋण, अनुदान और प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया गया है। परंतु इन नीतियों में अक्सर सामाजिक बदलाव और संरचनात्मक सुधार को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जाती।

नीतिगत दृष्टिकोण में यह आवश्यक है कि केवल योजनाएँ घोषित न की जाएँ, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और स्थानीयकृत रणनीति पर भी ज़ोर दिया जाए। उदाहरण के लिए, ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए बाज़ार संपर्क, परिवहन सुविधा, और डिजिटलीकरण जैसे अवयवों को भी नीति में समाहित करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमिता को एकल-उद्देश्यीय कार्यक्रम की तरह देखने की बजाय उसे व्यापक लैंगिक समानता नीति के हिस्से के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और निर्णय-निर्माण जैसे अन्य सामाजिक आयामों से भी जुड़ सके।

नीति विश्लेषण यह भी दिखाता है कि कई योजनाएँ शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जबकि महिला उद्यमिता का सबसे बड़ा अविकसित क्षेत्र ग्रामीण भारत है। अतः विकेन्द्रीकृत नीति निर्माण और समुदाय आधारित मॉडल अपनाने की ज़रूरत है।

## 7. निष्कर्ष और सुझाव

### 7.1 मुख्य निष्कर्ष

- यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि महिला उद्यमिता केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। भारत में महिला उद्यमिता का विकास धीमी गति से हो रहा है, परंतु इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी है। महिला उद्यमी आज विभिन्न क्षेत्रों—जैसे कि कुटीर उद्योग, सेवा क्षेत्र, तकनीक आधारित स्टार्टअप और ग्रामीण उत्पादन—में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं।
- यह भी निष्कर्ष निकला कि महिला उद्यमिता का सकल घरेलू उत्पाद (GDP), रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है, विशेषकर उन वर्गों के लिए जो पारंपरिक रूप से हाशिये पर रहे हैं।
- हालाँकि, यह क्षेत्र अब भी कई प्रकार की बाधाओं से ग्रस्त है—जैसे पूंजी की कमी, सामाजिक-सांस्कृतिक बंधन, तकनीकी प्रशिक्षण की अनुपलब्धता और नीति क्रियान्वयन में असमानता।
- इसके साथ ही, सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाएँ जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया आदि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका असर अब भी सीमित और असमान रूप से महसूस किया गया है।

### 7.2 भविष्य के लिए रणनीतिक सुझाव

- महिला उद्यमिता को प्रभावशाली रूप से बढ़ावा देने के लिए बहु-स्तरीय रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील और लचीला बनाना होगा, ताकि बिना गारंटी या जटिल प्रक्रियाओं के भी महिलाएं ऋण प्राप्त कर सकें।
- दूसरा, महिला-केंद्रित व्यवसायिक शिक्षा, डिजिटल कौशल और बाजार से जुड़ाव को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

- तीसरा, सरकार को केवल योजनाएं बनाने तक सीमित न रहकर, उनके स्थानीय क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और प्रभाव मूल्यांकन पर भी ज़ोर देना होगा।
- चौथा, सामाजिक स्तर पर मानसिकता में बदलाव लाने के लिए जन-जागरूकता, स्कूल पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता, और मीडिया के माध्यम से प्रेरक कहानियों का प्रचार आवश्यक है।
- पाँचवां, महिला उद्यमियों के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, मेंटरशिप, और उद्यमिता हब की स्थापना करनी चाहिए जहाँ वे आपस में सहयोग, साझेदारी और नवाचार कर सकें।
- अंततः, महिला उद्यमिता को केवल 'विकास का विषय' नहीं, बल्कि विकास की नीति का केंद्र बनाना होगा — तभी यह सशक्तिकरण, समानता और समृद्धि का स्थायी मार्ग बन सकेगा।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1. लिडिया, डी. ए., गोकुल, टी., और वर्षा, टी. एन. (2018). *परिवर्तन को सशक्त बनाना: भारत में सतत विकास लक्ष्यों और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली महिला उद्यमिता.*
2. शाह, एस., और अली, एम. एस. (2018). *महिला आर्थिक सशक्तिकरण और सीपीईसी में व्यापार की रणनीतिक भूमिका.* द जर्नल ऑफ रिसर्च रिव्यू, 2(3), 45–58.
3. चित्रा, वी., और तिलगवती, आर. (2017). *भारत में सतत विकास के लिए हरित उद्यमिता.*
4. साहि, पी., और कुमार, एस. (2017). *संभावनाओं को खोलना: उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए सरकारी पहल.* शोधपत्र, 2(6), 24–36.
5. विक्रम, डी. के., और आर. एस. आर. (2016). *ग्रामीण और शहरी उद्यमियों में तुलनात्मक अंतर्दृष्टि: शिवमोग्गा जिले के संदर्भ में.* जेजेईएम – जेएनएनसीई जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, विशेषांक 4, 45–53.
6. एलंगोवन, जी., पीटर, एस., और गुप्ता, ए. (2016). *लैंगिक वित्तीय अंतर को पाटने हेतु वित्तीय समावेशन में डिजिटल भागीदारी: भारत से साक्ष्य.* कोजेंट बिजनेस एंड मैनेजमेंट, 3(1), 2518492.
7. चक्रवर्ती, ए., और सेनगुप्ता, एस. (2016). *भारत में सामाजिक उद्यमिता की भूमिका: एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य.* अकादमी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीडिंग्स, 2016(1), 105–113.
8. जैन, ए., पाटिल, आर., माथुर, डी., और गोयल, एस. (2015). *भारतीय स्वास्थ्य स्टार्टअप्स में महिला नेतृत्व और पेटेंट का विश्लेषण.* अकादमी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीडिंग्स, 2015(1), 112–119.
9. कैनेडी, ए. जे., शोभा, जे. के. एस., और मोहन, ए. (2015). *चेन्नई में एकल माताओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: नदी-आधारित आजीविकाओं का अध्ययन.* टेलर एंड फ्रांसिस.

10. चांगखम, डी., सिंह, एस. आर., और राम, डी. (2015). *मणिपुर में कृषि आधारित महिला उद्यमिता की संभावनाएँ.* जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, 8(2), 50–62.

11. चौहान, एन. (2015). *स्वयं सहायता समूहों की भूमिका के माध्यम से हरियाणा में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण.* शोध सामाजिक, 3(1), 29–35.

12. प्रियदर्शी, ए. (2015). *ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन में फिनटेक की भूमिका: अवरोध और अवसर.* लुंबिनी जर्नल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, 5(1), 60–71.